RNI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 308
दि. 12.03.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

साइबर ठगों पर डिजिटल शिकंजा: पांच साल में 24 लाख से ज्यादा शिकायतें, 8690 करोड़ रुपये बचाए

जाएनएस)। नइ दिल्ला। डाजटल लेनदेन और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते दायरे के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं, लेकिन इन अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने तकनीक और समन्वित कार्रवाई के जरिए मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार किया है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत Indian Cyber Crime Coordination Centre (आई4सी) ने पिछले पांच वर्षों में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा डिजिटल प्रहार किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1855 दिनों में करीब 24.65 लाख साइबर शिकायतें दर्ज की गईं और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से लगभग 8,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ठगों के हाथ में जाने से बचा ली गई।

डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वर्ष 2021 में इस समन्वित तंत्र को मजबूत रूप में लागू किया। इसके अंतर्गत तत्काल शिकायत दर्ज कराने और धोखाधड़ी की रकम को तुरंत ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1930 cyber fraud helpline शुरू किया गया। इस नबर क माध्यम स दश क किसा भी हिस्से में रहने वाला नागरिक साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकता है, जिससे संबंधित एजेंसियां तुरंत कार्रवाई कर सकें और रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोका जा सके।

साइबर अपराधों से निपटने के लिए आई4सी के अंतर्गत एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी निवारण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर कहा जाता है। यहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भुगतान एग्रीगेटरों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी प्लेटफॉर्म्स और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मिलकर काम करते हैं। इस समन्वित व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि जैसे ही किसी धोखाधड़ी की सूचना मिलती है, सभी संबंधित संस्थाएं मिलकर तत्काल कार्रवाई करें और अपराधियों द्वारा धन की हेराफेरी को रोका जा सके।

सरकार ने साइबर ठगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनके तकनीकी ढांचे पर भी सख्त कार्रवाई की है। 31 जनवरी 2026 तक लगभग 12.94 लाख सिम कार्ड और 3.03

लाख मोबाइल डिवाइस ब्लॉक किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई मुख्य रूप से उन नंबरों और उपकरणों पर की गई है, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधों में किया जा रहा था। इसके लिए दूरसंचार कंपनियों और जांच एजेंसियों के बीच तकनीकी समन्वय को भी मजबूत किया गया है।

इसी दिशा में Sanchar Saathi प्लेटफॉर्म और National Cyber Crime Reporting Portal के बीच सीधा तकनीकी जुड़ाव स्थापित किया गया है। इस एकीकृत प्रणाली के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नंबरों और उपकरणों की जानकारी तुरंत टेलीकॉम कंपनियों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वे आवश्यक कार्रवाई करते हुए एस नबरा आर डवाइस का ब्लाक कर दता हैं। इससे साइबर ठगों के नेटवर्क को कमजोर करने में काफी मदद मिली है।

सरकार ने साइबर अपराध के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए 10 सितंबर 2024 को 'संदिग्ध रजिस्टर' की शुरुआत की। इस डिजिटल डेटाबेस में अब तक लगभग 23.05 लाख संदिग्ध व्यक्तियों का डेटा दर्ज किया जा चुका है, जबकि करीब 27.37 लाख ऐसे बैंक खातों की जानकारी भी इसमें शामिल है जिन्हें 'म्यूल अकाउंट' कहा जाता है। ये ऐसे खाते होते हैं जिन्हें अक्सर दूसरों के नाम पर खोलकर साइबर अपराध में इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवस्था की मदद से बैंकों ने अब तक करीब 9,518 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन को सफलतापूर्वक अस्वीकार कर दिया है, जिससे संभावित वित्तीय नुकसान को रोका जा सका है।

साइबर अपराध के कुछ क्षेत्र देश में लंबे समय से हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। इनमें झारखंड का जामताड़ा, हरियाणा का मेवात और गुजरात का अहमदाबाद जैसे इलाके प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन क्षेत्रों म साक्रय गराहा पर कारवाइ क लए वशष संयुक्त साइबर समन्वय दल गठित किए गए हैं। ऐसे सात विशेष दल इन क्षेत्रों में लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहे हैं।

अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 'प्रतिबिंब' नामक एक डिजिटल मॉड्यूल का भी उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से अपराधियों के मोबाइल टावर लोकेशन और गतिविधियों को डिजिटल नक्शे पर ट्रैक किया जा सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से अब तक 21,857 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह तकनीक जांच एजेंसियों को अपराधियों के नेटवर्क तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

साइबर अपराध से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए केवल तकनीक ही नहीं बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन भी जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए CyTrain portal नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां साइबर अपराध की जांच से जुड़े आधुनिक तरीकों और तकनाका का प्राशक्षण दया जाता है। अब तक करीब डेढ़ लाख अधिकारी इस पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं और नियमित रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं।

इसके अलावा दिल्ली और असम में अत्याधुनिक डिजिटल जांच सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में विशेषज्ञ तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर की मदद से मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों से महत्वपूर्ण सबूत जुटाने में पुलिस की सहायता की जाती है। इससे जांच प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक हो गई है।

सरकार का मानना है कि डिजिटल लेनदेन के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर सुरक्षा को मजबूत करना बेहद जरूरी है। आई4सी के माध्यम से बनाई गई यह बहुस्तरीय व्यवस्था नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। अधिकारियों के अनुसार यदि नागरिक सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, तो साइबर अपराधियों पर और प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है।

रेलवे फाटक बने हाई-स्पीड ट्रेनों की रफ्तार में रोड़ा, आठ महीने में हटे सिर्फ 268 फाटक

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में तेज रफ्तार ट्रेन सेवाओं के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बीच हजारों रेलवे फाटक बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहे हैं। रेल नेटवर्क को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से फाटकों को हटाकर उनकी जगह रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) बनाने की योजना लंबे समय से चल रही है, लेकिन परियोजनाओं की धीमी रफ्तार पर अब सवाल उठने लगे हैं। संसद की एक महत्वपूर्ण समिति ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि जिस गति से काम होना चाहिए था, उसके मुकाबले प्रगति बेहद धीमी है। रेल संबंधी स्थायी समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीनों में रेलवे देशभर में केवल 268 मानवयुक्त रेलवे फाटक ही हटा पाया है। यह संख्या उस बड़े लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम है, जिसके तहत हजारों फाटकों को समाप्त कर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई थी। समिति का मानना है कि इस धीमी प्रगति के कारण हाई-स्पीड और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों के संचालन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

समिति की अध्यक्षता भाजपा नेता C. M. Ramesh कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता वाली इस समिति ने रेलवे की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ब्रॉड गेज लाइनों से मानवरहित फाटक तो वर्ष 2019 तक पूरी तरह समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन मानवयुक्त फाटकों को हटाने की प्रक्रिया अभी भी काफी पीछे चल रही है। समिति ने कहा कि जब रेलवे देश में तेज रफ्तार ट्रेनों का नेटवर्क विकसित करने की बात कर रहा है, तब यह जरूरी है कि लेवल क्रॉसिंग जैसी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाए।

समिति के अनुसार जनवरी 2026 तक देश में ब्रॉड गेज लाइनों पर कुल 16,231 मानवयुक्त रेलवे फाटक अभी भी सक्रिय हैं। ये फाटक न केवल ट्रेनों की गति को सीमित करते हैं, बल्कि कई बार दुर्घटनाओं की वजह भी बन जाते हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि जब किसी ट्रैक पर लेवल क्रॉसिंग मौजूद होती है तो ट्रेनों की गति को नियंत्रित रखना पड़ता है, क्योंकि वहां सड़क यातायात भी होता है। यही कारण है कि हाई-स्पीड ट्रेन सेवाओं के विस्तार के लिए इन फाटकों को हटाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

भारतीय रेलवे का संचालन और विस्तार देश के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्क में से एक है, जिसका संचालन Indian Railways द्वारा किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने ट्रैक अपग्रेडेशन, विद्युतीकरण और आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली जैसे कई बड़े सुधार किए हैं। लेकिन लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने का काम अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रेलवे की योजना है कि इन फाटकों को हटाकर उनकी जगह आरओबी और आरयूबी बनाए जाएं, जिससे सड़क और रेल यातायात एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाएं और ट्रेनों को बिना रुकावट के चलाया जा सके।

हालांकि समिति ने यह भी कहा है कि केवल परियोजनाओं की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता पर भी ध्यान देना जरूरी है। रिपोर्ट में कई ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है जहां बनाए गए अंडर ब्रिज मानसून के दौरान जलभराव के कारण तालाब जैसे बन जाते हैं। बारिश के मौसम में इनमें पानी भर जाने से सड़क यातायात बाधित हो जाता है और कई बार लोगों को वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़ते हैं। समिति का मानना है कि इस तरह की समस्याएं योजना और निर्माण प्रक्रिया में तकनीकी खामियों की ओर इशारा करती हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरओबी और आरयूबी का निर्माण करते समय बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। यदि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो मानसून के दौरान ये संरचनाएं उपयोग के बजाय समस्या का कारण बन सकती हैं। समिति ने रेलवे से कहा है कि वह इन परियोजनाओं के डिजाइन और निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करे, ताकि हर मौसम में उनका उपयोग सुरक्षित और सुगम बना रहे।

समिति की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कई परियोजनाएं राज्यों और रेलवे के बीच लागत साझा करने की व्यवस्था के कारण अटक जाती हैं। वर्तमान में देशभर में कुल 4,769 आरओबी और आरयूबी परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से कई परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, प्रशासनिक स्वीकृतियों और वित्तीय हिस्सेदारी जैसी वजहों से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कई राज्यों द्वारा अपने हिस्से की राशि समय पर उपलब्ध न कराने के कारण करीब 30 से 35 प्रतिशत परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जब किसी आरओबी या आरयूबी का निर्माण किया जाता है तो उसमें राज्य सरकार और रेलवे दोनों की वित्तीय भागीदारी होती है। कई मामलों में भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों पर होती है। यदि इन प्रक्रियाओं में देरी होती है तो पूरी परियोजना प्रभावित होती है और निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता।

समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। इसके अलावा परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की भी जरूरत बताई गई है, जिससे समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जा सके।

सहकारिता मॉडल से बदलेगा टैक्सी सेक्टर 'भारत टैक्सी' का देशभर में होगा विस्तार

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के परिवहन क्षेत्र में सहकारिता मॉडल को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 'भारत टैक्सी' सेवा को आने वाले दो से तीन वर्षों के भीतर देशभर में विस्तारित करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत यह राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म केवल बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे धीरे-धीरे छोटे शहरों और प्रखंड स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि सहकारी ढांचे पर आधारित यह सेवा टैक्सी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ यात्रियों को भी एक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करेगी।

बुधवार को संसद के उच्च सदन Rajya Sabha में प्रश्नकाल के दौरान इस योजना से जुड़ी जानकारी साझा की गई। सरकार ने बताया कि 'भारत टैक्सी' नामक यह प्लेटफॉर्म सहकारी समितियों के संयुक्त प्रयास से संचालित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य निजी टैक्सी कंपनियों के प्रभुत्व को संतुलित करना है। सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में टैक्सी सेवाओं के क्षेत्र में कुछ निजी कंपनियों का अत्यधिक प्रभाव है, जिससे ड्राइवरों को अक्सर कमाई और अधिकारों के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सहकारिता आधारित यह पहल ड्राइवरों को एक नया और बेहतर विकल्प प्रदान कर सकती है।

सहकारिता राज्य मंत्री Krishan Pal Gurjar ने सदन में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य टैक्सी चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें निजी कंपनियों के एकाधिकार से राहत दिलाना है। उन्होंने बताया कि सहकारी मॉडल के तहत ड्राइवर केवल सेवा प्रदाता ही नहीं होंगे, बल्कि वे इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार भी बनेंगे। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी आय के साथ-साथ प्लेटफॉर्म में स्वामित्व का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। मंत्री ने कहा कि 'भारत टैक्सी' सेवा को आधुनिक तकनीक के अनुरूप विकसित किया गया है और इसे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस ऐप के जरिए यात्री आसानी से टैक्सी बुक कर सकते हैं और ड्राइवर भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से यात्रियों से जुड़ सकते हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से यह सेवा पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी, जिससे यात्रियों और ड्राइवरों दोनों को लाभ होगा।

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल की गई है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में इस सेवा को Delhi Police की सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सरकार का कहना है कि सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यात्रियों के विश्वास को बनाए रखना इस योजना की प्राथमिकता होगी।

सरकार के अनुसार 'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत सीमित शहरों से की गई थी, लेकिन इसे यात्रियों और ड्राइवरों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फिलहाल यह सेवा दिल्ली-एनसीआर के अलावा गुजरात के कई प्रमुख शहरों—अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ और द्वारका—में संचालित हो रही है। इन क्षेत्रों में सेवा शुरू होने के बाद धीरे-धीरे अधिक ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते जा रहे हैं। अब तक करीब चार लाख ड्राइवर इस पहल का हिस्सा बन चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि टैक्सी चालकों के बीच इस सेवा के प्रति रुचि बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सहकारिता आधारित यह मॉडल देश के परिवहन क्षेत्र में एक नई दिशा दे सकता है। अभी तक टैक्सी सेवाओं के क्षेत्र में निजी कंपनियों का दबदबा रहा है, जहां ड्राइवर अक्सर प्लेटफॉर्म शुल्क और अन्य शर्तों के कारण अपनी आय का बड़ा हिस्सा कंपनियों को देने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन सहकारी ढांचे में संचालित होने वाली सेवाओं में लाभ का बड़ा हिस्सा सीधे ड्राइवरों और संबंधित सदस्यों तक पहुंच सकता है।

'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत पिछले महीने केंद्रीय सहकारिता मंत्री Amit Shah द्वारा की गई थी। यह पहल देश की आठ प्रमुख सहकारी समितियों के संयुक्त उपक्रम के रूप में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसा परिवहन प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो ड्राइवरों के हितों की रक्षा करे और यात्रियों को भरोसेमंद सेवा प्रदान करे।

सरकार का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल होता है तो यह देश में सहकारिता आंदोलन को भी नई ऊर्जा दे सकता है। सहकारिता के माध्यम से कृषि, बैंकिंग और डेयरी क्षेत्र में पहले ही कई सफल उदाहरण सामने आ चुके हैं। अब परिवहन क्षेत्र में भी इसी मॉडल को अपनाकर एक नया विकल्प विकसित करने की कोशिश की जा रही है।

आने वाले वर्षों में 'भारत टैक्सी' सेवा का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले इसे प्रमुख महानगरों और बड़े शहरों में मजबूत किया जाएगा, उसके बाद मध्यम और छोटे शहरों तक पहुंचाया जाएगा। अंततः लक्ष्य यह है कि देश के प्रखंड स्तर तक इस सेवा को उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। सरकार को उम्मीद है कि सहकारी ढांचे पर आधारित यह पहल न केवल टैक्सी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी, बल्कि लाखों ड्राइवरों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा करेगी। साथ ही यात्रियों को भी अधिक विकल्प और बेहतर सेवा मिलने की संभावना बढ़ेगी।

13 साल की पीड़ा का अंत: सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 'सम्मानजनक मृत्यु' पर ऐतिहासिक टिप्पणी

जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने इच्छामृत्यु से जुड़े एक संवेदनशील मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक 31 वर्षीय युवक को 'सम्मान के साथ मृत्यु' का अधिकार देने की अनुमति दी है। अदालत का यह निर्णय कानून, चिकित्सा नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने वाला माना जा रहा है। करीब 13 वर्षों से कोमा की स्थिति में जीवन बिता रहे गाजियाबाद निवासी हरीश राणा के मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिससे उनके परिवार को लंबे समय से चल रही मानसिक और आर्थिक पीड़ा से राहत मिलने की उम्मीद है।

हरीश राणा का जीवन 2013 में एक हादसे के बाद पूरी तरह बदल गया था। वह उस समय चंडीगढ़ स्थित Panjab University के छात्र थे और पढ़ाई में बेहद प्रतिभाशाली माने जाते थे। बताया जाता है कि वह अपने बैच के टॉपर भी रहे थे। लेकिन एक दुर्घटना में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद उनका शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के बाद उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया नामक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें व्यक्ति का पूरा शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो जाता है और वह न बोल सकता है, न ही सामान्य रूप से महसूस कर सकता है। उस समय से लेकर आज तक वह कोमा की स्थिति में ही जीवन बिता रहे थे।

पिछले 13 वर्षों से हरीश के माता-पिता अपने बेटे के इलाज और देखभाल के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को ठीक करने की उम्मीद में अपनी जमा पूंजी और संपत्ति तक खर्च कर दी। समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। लंबे समय तक मशीनों और चिकित्सा उपकरणों के सहारे जीवन बनाए रखने की इस प्रक्रिया ने परिवार को मानसिक रूप से भी बेहद थका दिया था।

समय बीतने के साथ हरीश की स्थिति और भी जटिल हो गई। उनके शरीर पर गंभीर बेडसोर बनने लगे थे और डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कर दिया था कि उनके ठीक होने की संभावना लगभग शून्य है। इस स्थिति में परिवार ने भारी मन से अदालत का दरवाजा खटखटाया और बेटे को 'सम्मानजनक मृत्यु' देने की अनुमति मांगी। यह एक बेहद कठिन और भावनात्मक निर्णय था, लेकिन माता-पिता का कहना था कि वे अपने बेटे को इस तरह की असहनीय स्थिति में और लंबे समय तक नहीं देख सकते। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति J. B. Pardiwala ने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। फैसला सुनाते समय उन्होंने अंग्रेजी साहित्यकार William Shakespeare के प्रसिद्ध नाटक Hamlet की मशहूर पंक्ति "To be or not to be" का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न केवल कानूनी ही नहीं बल्कि गहरे मानवीय और नैतिक पहलुओं से भी जुड़ा होता है।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के Article 21 of the Constitution of India के तहत नागरिकों को केवल सम्मान के साथ जीने का अधिकार ही नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी निहित है। जब किसी मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती और वह पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हो जाता है, तब उसे जबरन जीवित रखना कई बार अमानवीय भी माना जा सकता है। इस मामले में अदालत ने 'पैसिव यूथेनेशिया' यानी निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि मरीज को कोई घातक दवा या इंजेक्शन दिया जाए। इसके बजाय मरीज को जीवन देने वाली कृत्रिम सहायता, जैसे वेंटिलेटर या अन्य चिकित्सा उपकरणों को धीरे-धीरे हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु हो सके। अदालत ने इस प्रक्रिया को बेहद सावधानी और चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान All India Institute of Medical Sciences (एम्स) को निर्देश दिया है कि चिकित्सा मानकों का पालन करते हुए हरीश राणा के जीवनरक्षक सपोर्ट सिस्टम को क्रमिक रूप से हटाया जाए, ताकि उनकी मृत्यु प्राकृतिक और गरिमापूर्ण तरीके से हो सके। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी प्रक्रिया में मरीज की गरिमा और परिवार की भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। अदालत ने कहा कि भारत में इच्छामृत्यु से जुड़े मामलों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट और व्यापक कानून नहीं है। फिलहाल यह व्यवस्था मुख्य रूप से 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर चल रही है। अदालत ने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर एक स्पष्ट और विस्तृत कानून बनाया जाए, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में परिवारों और डॉक्टरों को स्पष्ट कानूनी दिशा मिल सके।

अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टरों का प्राथमिक कर्तव्य मरीज का इलाज करना और जीवन बचाना होता है। लेकिन जब चिकित्सा विज्ञान स्वयं यह स्वीकार कर ले कि किसी मरीज के स्वस्थ होने की संभावना समाप्त हो चुकी है, तब उसे मशीनों के सहारे अनिश्चितकाल तक जीवित रखना हमेशा उसके सर्वोत्तम हित में नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में मानवीय संवेदनाओं और गरिमा को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक परिवार के लिए राहत का कारण नहीं बना है, बल्कि इच्छामृत्यु के मुद्दे पर देशभर में नई बहस और चर्चा को भी जन्म दे सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय चिकित्सा नैतिकता, मानवाधिकार और कानूनी व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संपादकीय

मुफ्त जमीं, महंगा इलाज

कभी चिकित्सा के पेशे को भगवान के दूसरे रूप में मानवता की सेवा का पर्याय माना जाता था। लेकिन आज मुनाफे की चांदी बटोरने की होड़ वाले अग्रणी पेशों में चिकित्सा व्यवसाय की गिनती होने लगी है। धन बटोरने की अंधी हवस में मानवता के तार-तार होने की इस व्यवसाय से जुड़ी खबरें आये दिन सुर्खियां बटोरती रहती हैं। यूं तो आज पैसे की अंतहीन भूख उन तमाम पेशों में नजर आती है जो सेवा-परोपकार व मनुष्यता के कल्याण में अग्रदूत माने जाते रहे हैं। लेकिन कुछ पेशे ऐसे हैं जो इंसानियत के रखवाले माने जाते रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा कि दिल्ली में जिन 51 अस्पतालों को रियायती जमीन दी गई थी और उन्होंने कुछ प्रतिशत गरीबों का इलाज मुफ्त करने का वायदा किया था, वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल, केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में एक नीतिगत फैसला लिया था, जिसके अंतर्गत दिल्ली में गरीब लोगों के लिये निजी अस्पतालों में एक सीमा तक मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई गई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि अस्पताल निजी हों या सरकारी, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिये ही बने होते हैं। इसी के मद्देनजर कई निजी अस्पतालों के निर्माण हेतु रियायती दर पर सरकार भूखंड उपलब्ध कराती है। जिसके चलते निजी अस्पतालों के कुछ दायित्व भी होते हैं। जिसमें निर्धन मरीजों के उपचार हेतु निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। यही वजह थी कि साल 2018 में भी, देश की शीर्ष अदालत ने रियायती जमीन हासिल करने वाले अस्पतालों को नसीहत दी थी कि गरीब लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरताने वालों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने को कहा था। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चेताने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर इस बाबत निगरानी करने वाले सरकारी विभाग भी आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। इस गंभीर मुद्दे की बार-बार अनदेखी किए जाने से खिन्न देश की शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली में रियायती दामों में प्लॉट लेने वाले 51 हॉस्पिटलों को नोटिस भेजकर अपना दायित्व न निभाने वालों को इसकी वजह बताने को कहा गया है। कोर्ट ने चेताया है कि अस्पताल के मालिकों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए! यह विडंबना है कि केंद्र व दिल्ली सरकार इस गंभीर मामले में उदासीन नजर आती हैं। विसंगति देखिए कि जिस दायित्व का निर्वहन सरकारों को करना चाहिए था, उस पर देश के सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने पड़ रहे हैं। जो हमारे तंत्र की काहिली को ही उजागर करता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले में इस बात का प्रावधान था कि रियायती कीमत पर जमीन पाने वाले अस्पतालों को आंतरिक रोगी विभाग में न्यूनतम दस प्रतिशत और ओपीडी में पच्चीस प्रतिशत गरीबों का इलाज मुफ्त करना होगा। जिससे जुड़ी जवाबदेही पूरी करने को शीर्ष अदालत ने 2018 में भी चेताया था। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। यही वजह है कि पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने इन अस्पतालों को नोटिस भिजवाए हैं। साथ ही अवज्ञा करने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इन निजी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके, पहली जवाबदेही सरकार की बनती है। यदि सरकार की नियामक एजेंसियां सख्ती दिखाती तो क्या मजाल थी कि निजी अस्पताल अपने वायदे से मुकर जाते। बाकायदा, ऐसे मामलों में उदासीनता दिखाने वाले सरकारी अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और लापरवाही दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। निस्संदेह, इन हालातों के चलते ही आम जनता का तंत्र से भरोसा उठता है। यदि सरकारी तंत्र निगरानी व जवाबदेही तय करने में चुस्ती दिखाता तो कई गरीब मरीजों का जीवन बचाया जा सकता था। आज जीवन रक्षा से जुड़ी चिकित्सा सुविधाएं इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर साल लाखों लोग खर्चीले इलाज कराने के चलते गरीबी के दलदल में धंस जाते हैं।

समरसता की चेतना का पोषण दूर करेगा विभाजन

"समाज किसी एक व्यक्ति, समुदाय या समूह से नहीं बनता; उसका प्रत्येक अंग राष्ट्र-निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः आवश्यक है कि हम जातिगत पहचान से ऊपर उठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी प्रतिभा और उसके चरित्र की विशेषताओं को महत्व दें।"

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित नए नियमों को लेकर देशभर में विवाद पूरी तरह थमा नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर शिक्षाविदों, छात्र संगठनों और आम नागरिकों तक, विभिन्न स्तरों पर इस प्रस्ताव का विरोध दिखाई दे रहा है। आलोचकों का मानना है कि इन नियमों से उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और शैक्षणिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जबकि सरकार और आयोग का तर्क है कि ये बदलाव शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित न रहकर सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है।

इस विरोध की तीव्रता का अंदाज़ा राजधानी दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से लगाया जा सकता है। जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नियमों का खुलकर विरोध किया। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पूर्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन्स, 2026' के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर ने व्यापक बहस को उत्पन्न कर दिया। अवांछित तर्कों के बीच हमें एक गंभीर विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव उस रूप में विद्यमान है, जिस रूप में यह प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है?

सत्ताईस वर्षों के अध्यापन अनुभव और हजारों विद्यार्थियों के निकट संपर्क के आधार पर मेरा अनुभव रहा है कि महाविद्यालयीन परिसर जातिगत भेदभाव से मुक्त सामाजिक संरचना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वहां का वातावरण मूलतः संवाद, सहभागिता और मित्रता के आधार पर विकसित होता है, जहां पारस्परिक संबंध जातिगत पहचान के बजाय मानवीय संपर्क और साझा शैक्षणिक जीवन से निर्मित होते हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय समाज आज जातिगत विमर्श के ऐसे जाल में उलझता जा रहा है, जहां पूर्व धारणाएं प्रायः तथ्यों पर भारी पड़ती प्रतीत होती हैं। हम वास्तविकताओं की शांत और गहन पड़ताल करने के बजाय प्रचलित मान्यताओं को ही अंतिम सत्य मान लेने की प्रवृत्ति विकसित कर चुके हैं।

यह भी एक व्यापक धारणा बन गई है कि भारतीय परंपराएं स्वयं जातिगत भेदभाव का पोषण करती रही हैं परंतु क्या यह सत्य है? या ऐसा कुछ है जिससे हम परिचित नहीं हैं। एएल बाशम ने 1954 में 'द वन्डर दैट वाज इण्डिया' में लिखा था कि 'मध्य युग के पूर्व भारत में जाति व्यवस्था सरल थी।' बहुत से उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जहां वर्ग परिवर्तित होता रहा है। कार्य को बदलने पर सामाजिक स्थिति बदलती रहती है। वैदिक वाङ्मय और प्राचीन संस्कृत साहित्य में कहीं भी जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता के उदाहरण परिलक्षित नहीं होते हैं। शूद्र' शब्द को 'क्षुद्र' से बना हुआ मानना भाषाशास्त्रीय रूप से प्रामाणित नहीं है। इसकी व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, अतः इसे सीधे 'हीन' अर्थ से जोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता।

अथर्ववेद के शब्दों की निरुक्ति में अपने श्रम के स्वेद (पसीने) से विविध उत्पादकीय कार्य में रत वर्ग को शूद्र कहा गया है। अर्थात् परिश्रमपूर्वक विविध प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन में रत (संलग्न) रहने वाले वर्ग को शूद्र कहकर संबोधित किया गया। इसमें किंचित भी संशय नहीं कि भारत पर हुए बाहरी आक्रमणों से पूर्व अपने उत्पादन कार्यों के प्रतिफल के स्वरूप शूद्र का समाज में आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च स्थान था। इसलिए कामन्दक नीतिसार में कहा गया है कि राजा को नया नगर बसाते समय शूद्र जो कि विभिन्न मूल्यवान वस्तुएं उत्पादित करते हैं उन्हें व वैश्य जो उन वस्तुओं के व्यापार से आय उत्पन्न करके राजस्व बढ़ाते हैं उन्हें अधिक संख्या में बसाना चाहिए। एगंस मेड्सिन ने अपने अध्ययन में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि विश्व का एक-तिहाई उत्पादन भारत में होने व प्राचीन वाङ्मय के अनुसार समग्र उत्पादन का दायित्व शूद्रों के नियंत्रण में होने से ही शूद्र प्राचीन काल से ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि यकायक शूद्र निम्न श्रेणी में कैसे अवस्थित हो गए?

अगर इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह विदित होगा कि इस वर्ग के पास कौशल और परिश्रम की निधि थी जिसे औद्योगीकरण के प्रभाव ने समाप्त कर दिया और परिणामस्वरूप रोजगार का अभाव उनकी आर्थिक विपन्नता का कारण बना। अंग्रेजों द्वारा उन्हें यह विश्वास निरंतर दिलाया गया कि उनके साथ जो कुछ भी नकारात्मक हुआ है और हो रहा है उसका कारण श्रेष्ठी वर्ग हैं। असत्य को निरंतर दोहराने पर वह सत्य प्रतीत होने लगता है। ब्रिटिश काल में बोया गया जातिगत विभाजन का बीज धीरे-धीरे एक ऐसी बेल में परिवर्तित हो गया, जो समाज के अनेक हिस्सों में फैलता चला गया। समय के साथ हमने यह कठोर सत्य भी भुला दिया। जब-जब समाज बिखरता है तब तक राष्ट्र की शक्ति क्षीण होती है।

इतिहास साक्षी है कि आंतरिक विभाजन किसी भी देश की प्रगति को धीमा कर देता है। हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित 'वर्ण व्यवस्था' 'जाति व्यवस्था' का आवरण पहन समय के साथ विकृत रूप ग्रहण करती गई और बीती कई सहस्राब्दियों में उसने भारतीय समाज के मूल आदर्श सहिष्णुता, सामाजिक समरसता तथा एकत्व भाव पर कुठाराघात किया। देश की सुदृढ़ता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि हम उन विखंडित इतिहास-कथनों और विभाजनकारी आख्यानों से स्वयं को मुक्त करें, जो हमें बार-बार यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं या किसी से निम्नतर हैं।

हमें यह स्मरण रखना होगा कि समाज किसी एक व्यक्ति, समुदाय या समूह से नहीं बनता; उसका प्रत्येक अंग राष्ट्र-निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः आवश्यक है कि हम जातिगत पहचान से ऊपर उठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी प्रतिभा और उसके चरित्र की विशेषताओं को महत्व दें। किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति व्यक्ति की क्षमता, परिश्रम, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक दृढ़ता पर आधारित होती है, न कि जन्माधारित पहचान पर। हम यह कैसे विस्मृत कर सकते हैं कि भारत वह राष्ट्र है जिसने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्घोष किया है। जब हमारी सभ्यता विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का आदर्श प्रस्तुत करती है, तब जाति की संकीर्ण विचारधाराओं में उलझे हमारे ही आदर्शों की खिल्ली उड़ाते प्रतीत हो रहे हैं। ध्यान रहे कि एक ऐसा समाज, जो स्वयं को लगातार खांचों में बांटता रहता है, अंततः अपनी सामूहिक शक्ति खो देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम विभाजन की मानसिकता को नहीं, बल्कि समरसता की चेतना को पोषित करें।

प्रेरणा

जब स्वामी विवेकानंद निर्भय होकर पागल सांड के सामने खड़े हो गए

मानव जीवन में भय और साहस का संघर्ष बहुत पुराना है। जब भी मनुष्य किसी संकट या अनिश्चितता के सामने खड़ा होता है, तब उसके भीतर छिपी हुई वास्तविक शक्ति सामने आती है। कई बार परिस्थितियाँ इतनी भयावह हो जाती हैं कि सामान्य व्यक्ति का मन डगमगा जाता है और वह स्वयं को बचाने के लिए किसी भी प्रकार से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने संकट के क्षणों में न केवल स्वयं को संभाला, बल्कि अपने आचरण से यह भी दिखा दिया कि सच्चा साहस भीतर से आता है। जब मनुष्य का हृदय ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से भरा होता है, तब वह भयावह परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रह सकता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन ऐसे ही अनेक प्रेरक प्रसंगों से भरा हुआ है, जिनमें उनका अद्भुत साहस, करुणा और ईश्वर में अडिग आस्था स्पष्ट दिखाई देती है। एक दिन स्वामी विवेकानंद अपने एक अंग्रेज मित्र और अपनी शिष्या कु. मूलर के साथ खुले मैदान में टहल रहे थे। वातावरण अत्यंत शांत और मनोहारी था। हल्की हवा चल रही थी और चारों ओर प्रकृति की हरियाली मन को आनंदित कर रही थी। तीनों आपस में बातचीत करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। उस समय उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में एक ऐसी घटना घटने वाली है, जो जीवन भर के लिए एक प्रेरणादायक स्मृति बन जाएगी। अचानक दूर से एक पागल सांड तेजी से उनकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी गति बहुत तेज थी और वह सीधे उसी दिशा में आ रहा था जहाँ स्वामी विवेकानंद, उनका अंग्रेज मित्र और कु. मूलर खड़े थे। सांड का विशाल शरीर, उसकी तेज चाल और उसके भीतर भरी हुई उग्रता देखकर किसी भी व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न होना स्वाभाविक था। जैसे-जैसे वह पास आता गया, स्थिति और अधिक गंभीर होती चली गई।

यह दृश्य देखते ही अंग्रेज मित्र घबरा गया। उसने तुरंत अपनी जान बचाने के बारे में सोचा और तेजी से दौड़ पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह पास की एक पहाड़ी के दूसरी ओर जाकर खड़ा हो गया, जहाँ से वह सुरक्षित दूरी बनाकर इस पूरे दृश्य को देख सकता था। दूसरी ओर कु. मूलर ने भी अपनी पूरी शक्ति से भागने की कोशिश की, लेकिन भय और घबराहट के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर गिर पड़ीं। अब उनकी स्थिति बेहद असहाय हो चुकी थी। सामने तेजी से दौड़ता हुआ पागल सांड और जमीन पर गिरी हुई एक महिला, जो स्वयं को बचाने में असमर्थ थी।

ऐसे समय में अधिकांश लोग शायद अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग जाते, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कुछ अलग ही निर्णय लिया। उन्होंने एक क्षण के लिए परिस्थिति को समझा और तुरंत यह महसूस किया कि यदि वे भी भागने लगेंगे तो कु. मूलर का जीवन गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने बिना देर किए स्वयं सांड के सामने खड़े होने का निश्चय किया। वे तेजी से आगे बढ़े और कु. मूलर के सामने इस प्रकार खड़े हो गए कि यदि सांड हमला करे तो सबसे पहले उन्हें ही उसका सामना करना पड़े। उस समय उनका चेहरा पूरी तरह शांत था। उनके मन में घबराहट या भय का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। वे स्थिर खड़े होकर सांड की ओर देख रहे थे। दूसरी ओर दूर खड़ा अंग्रेज मित्र यह सब देखकर हैरान था। बाद में उसने बताया कि उस समय उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि जब सांड स्वामी विवेकानंद से टकराएगा तो वह उन्हें कितनी दूर तक उछाल कर फेंकेगा। उसके मन में इस घटना का परिणाम पहले से ही भयावह दिखाई दे रहा था। लेकिन जो हुआ, वह बिल्कुल अलग था। सांड पूरी गति से दौड़ता हुआ स्वामी विवेकानंद के सामने पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह उनके करीब आया, वह अचानक ठहर गया। मानो उस निर्भीक व्यक्तित्व के सामने उसकी आक्रामकता स्वयं शांत हो गई हो। स्वामी विवेकानंद पूरी तरह स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर न भय था और न ही किसी प्रकार की बेचैनी। उनकी आँखों में गहरी शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ क्षणों तक सांड वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे-धीरे उसने अपना रुख बदला और पीछे हटने लगा। अंततः वह मुड़कर दूसरी दिशा में चला गया। इस प्रकार एक बड़ा खतरा बिना किसी नुकसान के टल गया। कु. मूलर सुरक्षित बच गईं और स्वामी विवेकानंद भी बिल्कुल शांत भाव से वहीं खड़े रहे। जब सांड दूर चला गया तो अंग्रेज मित्र धीरे-धीरे वापस लौटा। उसके चेहरे पर लज्जा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने स्वीकार किया कि वह भय के कारण भाग गया था और अपने मित्र को संकट में छोड़ दिया था। दूसरी ओर कु. मूलर के मन में गहरी श्रद्धा और आश्चर्य का भाव था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि इतनी खतरनाक स्थिति में भी उन्होंने इतना साहस कैसे बनाए रखा। जब सामने मृत्यु खड़ी थी, तब भी उनके मन में भय क्यों नहीं आया। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कराते हुए पास पड़े पत्थर के दो टुकड़े उठाए और उन्हें आपस में टकराया। पत्थरों के टकराने से हल्की चमक-सी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य के भीतर ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास होता है, तब वह स्वयं को ऐसे ही चमकते पत्थर के समान मजबूत और अडिग महसूस करता है। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि खतरे और मृत्यु के सामने भी उनका मन इसलिए नहीं डगमगाता, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के चरणों को छू लिया है। ईश्वर में उनका विश्वास उन्हें ऐसी शक्ति देता है कि कोई भी भय उन्हें विचलित नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद का यह कथन केवल एक दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि उनके जीवन की सच्चाई था। वे मानते थे कि जब मनुष्य अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, तब उसका मन स्थिर हो जाता है। उस समय भय का स्थान विश्वास ले लेता है और कमजोरी की जगह साहस जन्म लेता है। यह घटना केवल एक साहसिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन का एक गहरा संदेश भी देती है। यह बताती है कि सच्चा साहस बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास से पैदा होता है। जब मनुष्य के भीतर ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, तब वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाता नहीं। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसी सत्य का उदाहरण है। उन्होंने अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने साहस से यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी संकट का सामना निर्भय होकर कर सकता है। आज के समय में जब लोग छोटी-छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, यह प्रेरक प्रसंग हमें याद दिलाता है कि यदि हमारे भीतर विश्वास और आत्मबल है, तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती।

उत्तरप्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उपजे असंतोष को सूझबूझ पूर्वक पाट रहे हैं योगी आदित्यनाथ!

उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक पदों और सरकारी निकायों के पदों पर नियुक्तियों में विलंब मुख्य रूप से जातीय-क्षेत्रीय संतुलन, आंतरिक खींचतान और केंद्रीय नेतृत्व के मंथन के कारण हो रहा है। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा है, हालांकि मार्च 2026 तक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आलम यह है कि प्रदेश के सभी 16 नगर निगम में 10-10 मनोनीत होने वाले पार्षदों की नियुक्ति अटकी पड़ी है, जबकि तीन साल बीतने को है। विभिन्न बोर्डों की भी यही स्थिति है। इससे विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी की रणनीति पर भी असर पड़ना लाजिमी है, क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रस्साकशी में कार्यकर्ताओं में निराशा है। जहां तक विलंब के प्रमुख कारण की बात है तो जातीय एवं सामाजिक समीकरण इसकी पहली वजह है। भाजपा का ओबीसी करण होने से पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं में रोष गहराता जा रहा है। इसका असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर अवश्य पड़ेगा। लिहाजा पार्टी इससे पहले सभी वर्गों (ओबीसी, दलित, सवर्ण, खासकर ब्राह्मण राजपूत आदि) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में जुटी है, जिसपर प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मुखिया की खींचातानी से चयन अटका हुआ बताया जाता है।

वहीं पार्टी की आंतरिक गुटबाजी जैसे सांसदों-विधायकों के बीच खींचतान और केंद्रीय नेतृत्व व आरएसएस के बीच वैचारिक मतभेद (चुनावी साख बनाम संगठन अनुभव) से कई पद लंबित हैं। वहीं, सरकारी पदों पर देरी यानी निगमों, बोर्डों और आयोगों के 100+ रिक्त पदों पर पार्टी-संगठन व सरकार के बीच समन्वय की कमी, साथ ही योगी सरकार की मंजूरी का इंतजार है। अब तक ऐसा नहीं होने से जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष स्वाभाविक है।

खासकर वफादार कार्यकर्ता कार्यगत पुरस्कार न मिलने, लगातार चुनावी मेहनत के बावजूद पद न पाने से नाराज हैं; जिसके चलते कतिपय जिलों में सामूहिक इस्तीफे तक हुए। योगी-केशव जैसे नेताओं के बीच अनबन की अटकलें भी असंतोष बढ़ा रही हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि पंकज चौधरी दिसंबर 2025 में प्रदेश अध्यक्ष बने, जिससे 70+ जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। जबकि होली के बाद मिशन-2027 के तहत नई टीम, क्षेत्रीय अध्यक्षों में बदलाव की घोषणा संभावित है, जिसके दृष्टिगत पर्यवेक्षक भेजे गए हैं।

वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं के असंतोष को कम करने के लिए संगठनात्मक बदलाव, प्रत्यक्ष संवाद, प्रशिक्षण अभियान और पदों पर समायोजन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। ये प्रयास मुख्य रूप से 2027 चुनाव की तैयारी के तहत होली के बाद अब तेज हो रहे हैं। इस निमित्त कई संगठनात्मक कदम उठाए जा चुके हैं और कुछ प्रक्रिया धीन हैं। जहां तक नई टीम के गठन की बात है तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में होली बाद बड़े फेरबदल, जिलाध्यक्षों-क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्तियां, जातीय संतुलन बनाकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं, सरकारी पदों पर समायोजन यानी निगमों, बोर्डों, आयोगों के खाली पदों पर कार्यकर्ताओं की सूची तैयार है, और मिशन-2027 के तहत तोहफा के रूप में वितरण कार्य शेष रहने की खबर है।

संवाद एवं प्रशिक्षण प्रयास के तहत प्रत्यक्ष मुलाकातें हो रही हैं। 'कार्यकर्ता सर्वप्रथम' मंत्र से वन-टू-वन मैपिंग, वीआईपी संस्कृति खत्म कर रूठे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद; सीएम योगी विधायकों से नियमित बैठकें कर रहे हैं।वहीं डिजिटल एवं वैचारिक प्रशिक्षण के तहत कार्यकर्ताओं को डिजिटल हथियार से लैस करने का अभियान, और बूथ स्तर पर नीतियां-कार्यपद्धति सिखाना जारी है। आरएसएस-बीजेपी में समन्वय की कोशिशें परवान चढ़ी हुईं हैं।आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से योगी की मुलाकातें, कानपुर समन्वय बैठक में असंतोष मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके दृष्टिगत आंतरिक कलह सुलझाने की कोशिश जारी है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी संभालने के लिए प्रत्यक्ष बैठकें शुरू कर दी है। आरएसएस-बीजेपी समन्वय मंचों पर खुली चर्चा और जमीनी मुद्दों पर आश्वासन जैसे कदम उठाए हैं। मार्च 2026 तक गोरखपुर व कानपुर जैसी जगहों पर ये प्रयास तेज हुए। प्रत्यक्ष संवाद हो रहे हैं। खुद योगी ने 200+ विधायकों, सांसदों व पूर्व नेताओं से अलग-अलग मुलाकातें कीं, जहां उन्होंने पार्टी की हार के कारणों (कार्यकर्ता-सरकार डिस्कनेक्ट) को सुने और विपक्षी प्रचार पर जवाब देने को कहा। साथ ही जमीनी स्तर पर समस्याओं (जैसे अस्पताल बेड) के समाधान का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री की आरएसएस से समन्वय बैठकें भी चल रही हैं। गोरखपुर (मार्च 2026) में पदाधिकारियों से मन की बात सुनकर जवाब दिए, और एआई (AI) युग व कैशलेस इलाज जैसे सवाल हल किए। वहीं कानपुर (मार्च 2026) में आरएसएस के साथ बैठक में कार्यकर्ता सम्मान, यूजीसी नियमों से सवर्ण असंतोष, स्थानीय विवादों पर चर्चा हुई; साथ ही अनुशासनहीनता पर कार्रवाई व बेहतरी का आश्वासन दिया। जबकि अन्य प्रयास के तहत बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि एसआईआर (SIR) फॉर्म भरें, मतदाता जागरूकता कैंप लगाएं; और अफसरों से कार्यकर्ता शिकायतें दूर करने को कहा। साथ ही कार्यकर्ताओं से 'कैंडिड फीडबैक' भी लिया। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की रणनीति ने उत्तर प्रदेश भाजपा में आंतरिक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर क्षेत्रीय समन्वय बैठकों और प्रत्यक्ष संवाद से। इससे कार्यकर्ताओं की नाराजगी घटी और 2027 चुनाव की तैयारी एकजुट हुई। वहीं क्षेत्रीय समन्वय बैठकें भी हुईं।

अभियान

लक्ष्मी कृपा का मार्ग: भक्ति, पवित्रता और सदाचार से ही खुलते हैं सौभाग्य के द्वार

भारतीय सनातन परंपरा में यह विश्वास अत्यंत गहरा है कि मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आती, बल्कि उसके भीतर की श्रद्धा, उसके घर की पवित्रता और उसके आचरण की शुद्धता से भी जुड़ी होती है। हमारे ऋषि-मुनियों ने जीवन को एक साधना माना है और बताया है कि यदि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल नियमों का पालन करे, तो ईश्वर की कृपा उसके जीवन में सहज रूप से प्रकट होने लगती है। मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। यह माना जाता है कि जहां स्वच्छता, अनुशासन, विनम्रता और भक्ति का वातावरण होता है, वहां मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर निवास करती हैं। लेकिन जहां लापरवाही, गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां समृद्धि अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए हमारे पूर्वज हमेशा यह समझाते रहे हैं कि घर और जीवन दोनों को मंदिर के समान पवित्र बनाए रखना चाहिए।

आज के समय में जब जीवन अत्यधिक व्यस्त और भागदौड़ भरा हो गया है, लोग कई बार उन छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो जीवन की शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि केवल बड़े कर्म ही जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे छोटे-छोटे व्यवहार भी भाग्य की दिशा को प्रभावित करते हैं। वास्तु शास्त्र और धार्मिक परंपराओं में ऐसे कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि इन बातों की अनदेखी की जाए, तो धीरे-धीरे घर में अशांति, आर्थिक कठिनाई और मानसिक तनाव का वातावरण भी बन सकता है।

घर की रसोई को भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। यह केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है, बल्कि इसे मां अन्नपूर्णा का निवास भी कहा जाता है। जिस घर की रसोई स्वच्छ, व्यवस्थित और पवित्र रहती है, वहां भोजन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन कई लोगों की यह आदत होती है कि वे रात में भोजन करने के बाद जूठे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं और उन्हें सुबह साफ करने के लिए टाल देते हैं। यह देखने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह आदत शुभ नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि रात के समय रसोई को गंदा छोड़ देना मां अन्नपूर्णा का अनादर माना जाता है। जब रसोई में स्वच्छता बनी रहती है, तब घर में अन्न और धन दोनों की बरकत बनी रहती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा यह कहते आए हैं कि रात को सोने से पहले रसोई को साफ कर देना चाहिए और जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए।

घर के मुख्य द्वार का भी आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। मुख्य द्वार को घर का प्रवेश द्वार ही नहीं बल्कि शुभ ऊर्जा का मार्ग भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि संध्या के समय मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में स्वच्छता और प्रकाश होता है, वहां प्रवेश करती हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ादान रखा हो, जूते-चप्पल बिखरे हों या गंदगी हो, तो यह शुभ नहीं माना जाता। ऐसा वातावरण न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है बल्कि घर के सौभाग्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए मुख्य द्वार को हमेशा साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। कई घरों में यह परंपरा भी होती है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। दीपक की लौ अंधकार को दूर करती है और घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। यह दीपक मानो मां लक्ष्मी का स्वागत करने का एक पवित्र संकेत होता है।

घर में रखी वस्तुओं का भी हमारे जीवन पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। यदि घर में टूटा हुआ शीशा रखा हो या घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी हो, तो इसे भी शुभ नहीं माना जाता। टूटा हुआ कांच जीवन में असंतुलन और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। वहीं बंद घड़ी यह संकेत देती है कि घर में समय और ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। इसलिए यदि घर में ऐसी कोई वस्तु हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए या घर से हटा देना चाहिए। जब घर का वातावरण संतुलित और व्यवस्थित होता है, तब जीवन की दिशा भी सकारात्मक बनने लगती है।हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी को देवी का स्वरूप माना जाता है और भगवान विष्णु की प्रिय भी कहा जाता है। लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ऐसा विश्वास है कि जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए तुलसी के स्थान को अत्यंत स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। कई बार लोग अनजाने में तुलसी के पास झाड़ू, कूड़ेदान या जूते-चप्पल रख देते हैं, जो उचित नहीं माना जाता। तुलसी के पास दीपक जलाना, जल अर्पित करना और श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करना घर में आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और वातावरण को शांत तथा पवित्र बनाता है। संध्या का समय भी अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और इसे देवताओं की उपस्थिति का समय कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि इसी समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए इस समय घर का वातावरण शांत और भक्तिमय होना चाहिए। कई घरों में यह नियम होता है कि संध्या के समय झाड़ू-पोछा नहीं लगाया जाता। ऐसा माना जाता है कि इस समय घर की सफाई करने से घर की बरकत बाहर चली जाती है। इसके स्थान पर लोग संध्या के समय दीपक जलाते हैं, भगवान की आरती करते हैं और भजन-कीर्तन करते हैं। इससे घर का वातावरण पवित्र और आनंदमय बन जाता है। भोजन को भी भारतीय संस्कृति में ईश्वर का प्रसाद माना गया है। इसलिए भोजन को सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए। कई लोग सुविधा के कारण बिस्तर पर बैठकर भोजन करने लगते हैं, लेकिन इसे उचित नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर भोजन करने से घर में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ सकती है। भोजन को हमेशा उचित स्थान पर बैठकर और ईश्वर का स्मरण करते हुए ग्रहण करना चाहिए। जब भोजन को प्रसाद मानकर खाया जाता है, तब वह शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है।

इन सभी बातों का सार यही है कि जीवन में सुख और समृद्धि केवल बड़े प्रयासों से नहीं आती, बल्कि छोटी-छोटी आदतों से भी जुड़ी होती है। जब मनुष्य अपने घर और जीवन में स्वच्छता, अनुशासन और भक्ति को स्थान देता है, तब उसका जीवन स्वतः ही संतुलित और आनंदमय बन जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी बड़े यज्ञ या कठिन साधना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल श्रद्धा, पवित्रता और सदाचार ही पर्याप्त होते हैं।

जब घर में सुबह भगवान का स्मरण होता है, संध्या के समय दीपक जलता है, तुलसी के पास प्रार्थना होती है और घर का हर कोना स्वच्छ और व्यवस्थित रहता है, तब वह घर केवल एक निवास स्थान नहीं रहता बल्कि एक पवित्र धाम बन जाता है। ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और परिवार के सभी सदस्य सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं।

इसलिए यदि जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि की कामना है, तो आवश्यक है कि हम अपने जीवन में भक्ति, पवित्रता और सदाचार को स्थान दें। छोटी-छोटी आदतों में सुधार करके हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब मन में श्रद्धा हो, घर में स्वच्छता हो और व्यवहार में विनम्रता हो, तब मां लक्ष्मी की कृपा स्वयं मार्ग खोजकर हमारे जीवन में प्रवेश करती है और जीवन को आनंद, संतोष और समृद्धि से भर देती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साबरकांठा के नवलपुर से जिले को 72 करोड़ रुपए के 1999 विकास कार्यों की सौगात दी

मुख्यमंत्री ने साबरकांठा को स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित 'स्कॉच अवॉर्ड' की उपलब्धि के लिए बधाई दी

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को साबरकांठा जिले के विकास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए तलोद तहसील के आदर्श गांव नवलपुर से लगभग 72 करोड़ रुपए के 1999 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही साथ, मुख्यमंत्री ने नवलपुर ग्राम पंचायत के नए भवन और गांव के अमृत सरोवर पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि गुजरात सरकार के विकास के कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए भारी धनराशि खर्च कर रही है। उन्होंने अधिकारियों और नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि यदि सरकारी कार्य को अपना समझकर किया जाए, तो उसकी गुणवत्ता और जीवनकाल अपने आप बढ़ जाता है।

मुख्यमंत्री ने नवलपुर गांव को ग्रामीण विकास का उत्तम उदाहरण बताते हुए कहा कि इस गांव में सरपंच से लेकर सारे सदस्य महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण है। नवलपुर ने 'समरस गांव' के विचार को चरितार्थ करने के साथ ही पानी के मीटर जैसी आधुनिक सुविधाओं और सौ फीसदी सोलर सिस्टम अपनाकर देश को एक नई राह दिखाई है। मुख्यमंत्री ने साबरकांठा जिले से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा के भौगोलिक महत्व को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 8 करोड़ रुपए के खर्च से बने अत्याधुनिक 'साइंस पार्क' का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 1.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पार्क में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टावर, सनडायल और इंफोग्राफिक एग्जीबिशन हॉल जैसी सुविधाएं हैं, जो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा क्षेत्र में 'नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना' की सफलता के कारण विज्ञान संकाय के छात्रों में 19 फीसदी की वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कम वजन वाली गर्भवती

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- गुजरात सरकार के पास विकास के कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है
- यदि सरकारी काम को अपना समझकर किया जाए, तो उसकी गुणवत्ता और जीवनकाल अपने आप बढ़ जाता है
- नवलपुर गांव महिला सशक्तिकरण का श्रेष्ठ उदाहरण

महिलाओं के लिए लागू 'लालन-पालन' कार्यक्रम और बच्चों में टाइप-1 डायबिटीज के नियंत्रण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की इन दोनों पहलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित 'स्कॉच अवॉर्ड' दिया गया है, जो जिले के लिए गर्व की बात है।

शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने इस अवसर पर 'समरस, स्वच्छ और सोलर' गांव के रूप में नवलपुर की सराहना की और कहा कि इस गांव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार किया है। उन्होंने 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित साइंस पार्क को आने वाली पीढ़ी के लिए विज्ञान का जीवंत केंद्र बताया, जो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा।

श्री वाजा ने आगे कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर के बच्चों तक श्रेष्ठ शिक्षा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और जिले में 518 लाख रुपए के खर्च से 26 नए क्लासरूम का निर्माण इस दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे सरकारी संपत्ति को अपना समझते हुए उनका रखरखाव करें।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती भारतीबेन ने नवलपुर गांव में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के साथ और जनभागीदारी के कारण ही नवलपुर गांव आज विकास का मॉडल बन पाया है। उन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान विकास कार्यों के लिए उदारता से अनुदान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने गर्व से कहा कि नवलपुर आज सिद्ध कर रहा है कि जब समाज और सरकार साथ मिलकर काम करते हैं, तो कैसे श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं।

प्रांतिज-तलोद के विधायक श्री गजेन्द्रसिंह परमार ने नवलपुर की उपलब्धियों को महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि नवलपुर ने गोबर बैंक बनाकर और 100 फीसदी सोलर सिस्टम अपनाकर एक आदर्श गांव का निर्माण किया है। उन्होंने तलोद बस डिपो की वर्षों पुरानी समस्या का सुखद समाधान कर नए डिपो का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और गांव की स्वच्छता के लिए किए गए व्यवस्थित आयोजन की सराहना की।

हिम्मतनगर के विधायक श्री वी.डी. झाला ने कहा कि वर्ष 2001 से मोदी युग में विकास कार्यों के लिए अनुदान की कभी कमी नहीं रही है। उन्होंने सरकार के किसान-उन्मुख दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि मानसून में हुए नुकसान के एवज में राहत पैकेज देकर सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने गर्व से कहा कि सुजलाम सुफलाम योजना के कारण जिले में पानी की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो गया है और पूरा साबरकांठा जिला हरा-भरा बन गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 1999 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें परिवहन विभाग के 1390 लाख रुपए के कार्य और सामान्य प्रशासन विभाग के 3667 लाख रुपए के कार्य शामिल हैं।

कलेक्टर श्री ललित नारायण सिंह सांदू ने स्वागत भाषण दिया जबकि प्रांतिज की प्रांत अधिकारी सुश्री आयुषी जैन ने आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर विधायक श्री रमणलाल वोरा, राज्य वित्त आयोग के सदस्य श्री जे.डी. पटेल, अग्रणी श्री कनुभाई पटेल, जिला विकास अधिकारी श्री हर्षद वोरा, पुलिस अधीक्षक डॉ. पार्थराजसिंह गोहिल और निवासी अपर कलेक्टर सुश्री कृष्णा वाघेला सहित बड़ी संख्या में ग्रामजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साबरकांठा के सलाल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क का उद्घाटन किया

- मुख्यमंत्री ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क का दौरा कर पार्क के भौगोलिक और खगोलीय महत्व के बारे में जानकारी हासिल की
- पार्क को 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5,930 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया गया

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को साबरकांठा जिले के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ ही जिले के सलाल गांव में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर (कर्क रेखा) साइंस पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, शिक्षा मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा और कई विधायक मौजूद रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क का जायजा लिया और पार्क के भौगोलिक एवं खगोलीय महत्व के बारे में जानकारी हासिल कर विद्यार्थियों के साथ संवाद किया।

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (गुजकोस्ट) ने कर्क रेखा के वैज्ञानिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने, समझ विकसित करने और विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए इसे एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं शोध बिंदु के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क बनाया है।

साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर हाईवे पर सलाल गांव में जहां से कर्क रेखा गुजरती है, वहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क को 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5,930 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस पार्क को कर्क रेखा के भौगोलिक और खगोलीय महत्व को प्रकाशित करने और आगंतुकों को पृथ्वी-सूर्य संबंधों, मौसमी बदलावों और संबंधित वैज्ञानिक घटनाओं को समझने

का आकर्षक अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर स्थित होने के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क सभी आगंतुकों के लिए वैज्ञानिक शिक्षा और विज्ञान पर्यटन के केंद्र के रूप में सेवा देगाएं। गुजकोस्ट ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के छात्रों को इस पार्क को देखने का आमंत्रण दिया है। साइंस पार्क कल यानी गुरुवार से सुबह 9.00 से शाम 6.00 बजे तक सभी आगंतुकों के लिए खुला रहेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित अन्य महानुभावों ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क के प्रांगण में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया।

कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती, साबरकांठा के कलेक्टर श्री ललित नारायणसिंह सांदू, जिला विकास अधिकारी और विज्ञान एवं पौद्योगिकी विभाग तथा गुजकोस्ट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का बढ़ता भरोसा, एयूएम 82 लाख करोड़ के पार

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में म्यूचुअल फंड योजनाओं के प्रति निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। शेयर बाजार में समय-समय पर आने वाले उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशकों की भागीदारी बनी हुई है और यही वजह है कि फरवरी महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया। ताजा आंकड़ों के अनुसार फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुल निवेश 25,965 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो जनवरी महीने में आए 24,013 करोड़ रुपये के निवेश की तुलना में करीब 8.2 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि इस बात का संकेत देती है कि बाजार में अस्थिरता के बावजूद निवेशक दीर्घकालिक निवेश के रूप में इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक मजबूत विकल्प मान रहे हैं।

ये आंकड़े देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के शीर्ष संगठन Association of Mutual Funds in India (एएमएफआई) द्वारा जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों का रुझान लगातार इक्विटी आधारित योजनाओं की ओर बना हुआ है और बाजार में हलचल के बावजूद निवेश की गति धीमी नहीं पड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीते कुछ वर्षों में वित्तीय साक्षरता में बढ़ोतरी, डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म की सुविधा और नियमित निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण म्यूचुअल फंड उद्योग को लगातार मजबूती मिल रही है। फरवरी के आंकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि म्यूचुअल फंड उद्योग का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। फरवरी के दौरान यह मासिक आधार पर लगभग 1.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ करीब 81 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। उद्योग के कुल एयूएम का स्तर अब 82 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि देश में निवेश संस्कृति तेजी से विकसित हो रही है और निवेशक धीरे-धीरे पारंपरिक बचत साधनों से आगे बढ़कर बाजार आधारित निवेश विकल्पों को अपना रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार म्यूचुअल फंड उद्योग की परिसंपत्तियों में लगातार बढ़ोतरी का मुख्य कारण निवेशकों की निरंतर भागीदारी है। पिछले कुछ वर्षों में लाखों नए निवेशक म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं और बड़ी संख्या में लोग नियमित निवेश योजना यानी एसआईपी के माध्यम से हर महीने निवेश कर रहे हैं। इससे उद्योग में स्थिर और दीर्घकालिक पूंजी का प्रवाह बना हुआ है, जो बाजार में स्थिरता लाने में भी मदद करता है। फरवरी के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड की विभिन्न श्रेणियों में निवेश बढ़ने का रुझान देखा गया। लार्ज कैप फंड में फरवरी के दौरान लगभग 2,111 करोड़ रुपये का निवेश आया, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा करीब 2,005 करोड़ रुपये था। इसका मतलब है कि निवेशक बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करने वाली योजनाओं पर भी भरोसा बनाए हुए हैं। लार्ज कैप फंड को आमतौर पर अपेक्षाकृत स्थिर और कम जोखिम वाला माना जाता है, इसलिए कई निवेशक अपने पोर्टफोलियो में इन योजनाओं को शामिल करना पसंद करते हैं। मिड कैप फंड में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। फरवरी में इस श्रेणी में निवेश बढ़कर लगभग 4,003 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि जनवरी में यह 3,185 करोड़ रुपये था। मिड कैप कंपनियों को भविष्य की संभावनाओं के लिहाज से काफी आकर्षक माना जाता है क्योंकि इनमें विकास की क्षमता अधिक होती है। यही कारण है कि निवेशक जोखिम और संभावित रिटर्न के संतुलन को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं में भी निवेश कर रहे हैं।

स्मॉल कैप फंड में भी निवेश का प्रवाह बढ़ता दिखाई दिया। फरवरी में इस श्रेणी में निवेश लगभग 3,881 करोड़ रुपये रहा, जबकि जनवरी में यह 2,942 करोड़ रुपये था। स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश को अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाला माना जाता है, लेकिन लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना के कारण निवेशकों का रुझान इस श्रेणी की ओर भी बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे निवेशक भी अब धीरे-धीरे निवेश की विविधता को समझने लगे हैं और अपने निवेश को अलग-अलग श्रेणियों में बांट रहे हैं।

सोना वायदा 1100 रुपये और चांदी वायदा 6900 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा में 558 रुपये का ऊछाल

जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 170292.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 23948.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 146343.48 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 40200 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 5877.12 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 11882.25 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 163149 रुपये के भाव पर खूलकर, 163149 रुपये के दिन के उच्च और 161977 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 163303 रुपये के पिछले बंद के सामने 1100 रुपये या 0.67 फीसदी गिरकर 162203 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 612 रुपये या 0.46 फीसदी गिरकर 132241 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 81 रुपये या 0.48 फीसदी गिरकर 16628 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 162990 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 163123 रुपये और नीचे में 162000 रुपये पर पहुंचकर, 1121 रुपये या 0.69 फीसदी गिरकर 162155 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 163465 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 163800 रुपये और नीचे में 162700 रुपये पर पहुंचकर, 163778 रुपये के पिछले बंद के सामने 908 रुपये या 0.55 फीसदी गिरकर 162870 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 276988 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 276999 रुपये और नीचे में 270551 रुपये पर पहुंचकर, 277850 रुपये के पिछले बंद के सामने 6900 रुपये या 2.48 फीसदी औंधकर 270950 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 6835 रुपये या 2.42 फीसदी की गिरावट के साथ 275815 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 6950 रुपये या 2.46 फीसदी औंधकर 275802 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में 2138.92 करोड़ रुपये के ट्रेड

- कमोडिटी वायदाओं में 23948.25 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 146343.48 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 11882.25 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 40200 पॉइंट के स्तर पर

दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 8.15 रुपये या 0.67 फीसदी घटकर 1199.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मार्च वायदा 1.35 रुपये या 0.41 फीसदी घटकर 324.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 4.7 रुपये या 1.39 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 341.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 20 पैसे या 0.11 फीसदी चढ़कर 188.65 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 9972.89 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा 7717 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8224 रुपये और नीचे में 7596 रुपये पर पहुंचकर, 558 रुपये या 7.52 फीसदी बढ़कर 7979 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 555 रुपये या 7.48 फीसदी की तेजी के संग 7979 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 280.4 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 287.8 रुपये और नीचे में 278.7 रुपये पर पहुंचकर, 276.1 रुपये के पिछले बंद के सामने 8.9 रुपये या 3.22 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 285 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 8.7 रुपये या 3.15 फीसदी की मजबूती के साथ 285.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 985 रुपये के भाव पर खूलकर, 27 रुपये या 2.77 फीसदी की तेजी के संग 1000 रुपये प्रति किलो हुआ। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 6605.67 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 5276.58 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1360.05 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 472.01 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 3.70 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 297.59 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 8331.40 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1626.28 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 9.24 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10234 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61035 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 30351 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 423594 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61037 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6794 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18213 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 66076 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 28819 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 28118 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 40429 पॉइंट पर खूलकर, 40429 के उच्च और 40166 के नीचले स्तर को छूकर, 137 पॉइंट घटकर 40200 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 263.7 रुपये की बढ़त के साथ 703.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.4 रुपये की बढ़त के साथ 21.85 रुपये हुआ।

सोना मार्च 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 168 रुपये की गिरावट के साथ 444 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 350000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 504 रुपये की गिरावट के साथ 1054 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.77 रुपये की गिरावट के साथ 10 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 325 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.12 रुपये की बढ़त के साथ 7.96 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 140.1 रुपये की गिरावट के साथ 261.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.75 रुपये की गिरावट के साथ 17.5 रुपये हुआ।

सोना मार्च 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 6 रुपये की गिरावट के साथ 324 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 22.5 रुपये की गिरावट के साथ 1154.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.27 रुपये की बढ़त के साथ 22.8 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 325 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.5 रुपये की गिरावट के साथ 5.5 रुपये हुआ।

मलेशियाई प्रथब मुनियांडी के मुंह में 42 दांत: अपनी अनूठी प्राकृतिक संरचना के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज।

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। एक इंसान के मुंह में आमतौर पर 32 दांत होते हैं। जब से हमने पका हुआ खाना खाना शुरू किया है, विकास के कारण इन दांतों की संख्या कम होती जा रही है। और अब पूरे 32 स्वस्थ दांतों वाले लोग मिलना दुर्लभ हो गया है। ऐसे में, मलेशिया के रहने वाले प्रताप मुनियांडी नाम के एक व्यक्ति के मुंह में 32 से अधिक दांत हैं। 33 वर्षीय प्रताप, जो तेल और गैस उद्योग में इंजीनियर के रूप में काम करते हैं, को 2021 में पता चला कि उनके मुंह में सामान्य से अधिक दांत हैं। जब उन्होंने अपने दांत गिने, तो वे 38 निकले। स्वाभाविक रूप से, इतने सारे दांत देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि, उनके मसूड़ों में दर्द भी शुरू

हो गया।

शून्य त्रुटि एजेंसी

प्रथाभाई ने सोचा कि एक बेसिक चेक-अप करवा लेना अच्छा रहेगा, तो अचानक डेंटिस्ट ने बताया कि उन्हें जो दर्द हो रहा है, वह चार नए दांत उगने की वजह से है। हैरानी की बात यह है कि देखते ही देखते वे दांत भी उग आए और अब उनके मुंह में कुल दांतों की संख्या 42 हो गई है। प्रथाभाई कहते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि उनके मुंह में 42 दांत हैं। क्योंकि बाहर से देखने पर दांतों की बनावट घनी लेकिन साफ-सुथरी दिखती है। इस अनोखे प्राकृतिक उपहार के लिए प्रथाभाई का नाम हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा दांत वाले व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया है।

सूरत में फर्जी डॉक्टरों और अयोग्य चिकित्सा दुकानों की बाढ़ के बाद, महिला छात्रों की आत्महत्या के बाद व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

सूरत के विभिन्न इलाकों जैसे उधना, भेस्तान, उन, पांदेसरा, लिंबायत, दिंडोली, गोदादरा, कावस, हजीरा, मोरा आदि में औद्योगिक कारखानों और भोजनालयों में बड़ी संख्या में मजदूर और कारीगर काम करते हैं। जब ये मजदूर और कारीगर बीमार पड़ते हैं, तो वे अक्सर सिविल अस्पताल या मेडिकल अस्पताल जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें परेशान किया जाता है और उचित और सस्ता इलाज नहीं मिलता, इसलिए वे मजबूर होकर उस इलाके के अयोग्य डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर हो जाते हैं। ये अयोग्य डॉक्टर मरीजों को एक्सपायर्ड दवाइयां भी दे देते हैं। मरीजों को इसकी जानकारी नहीं होती और डॉक्टरों को भी नहीं। इस तरह इन इलाकों में अयोग्य और फर्जी डॉक्टरों की एक श्रृंखला टूट पड़ी है। सूरत शहर के सानिया इलाके में दो छात्राओं ने इंजेक्शन खाकर आत्महत्या कर ली है। इन छात्राओं की आत्महत्या से सूरत शहर में सनसनी फैल गई है। इन छात्राओं को ये इंजेक्शन कहाँ से मिले? किस मेडिकल स्टोर के मालिक ने इन मासूम लड़कियों को ये इंजेक्शन दिए, इसकी जांच होनी चाहिए। उन, भेस्तान, पांदेसरा, सचिन, लिंबायत, उधना, पीयूष प्वाइंट आदि इलाकों में अंधाधुंध मेडिकल स्टोर खुल गए हैं। कुछ अमीर लोग ऐसे मेडिकल स्टोर खोलने में निवेश करते हैं। और मेडिकल स्टोर चलाने के लिए योग्य फार्मासिस्टों की आवश्यकता के बावजूद, 8 से 10 किताबों की शिक्षा प्राप्त कर्मचारी इन स्टोरों में काम करते हैं। और ये कर्मचारी बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाइयां देते हैं। इस प्रकार, मेडिकल स्टोर चलाने वालों के पास भी डिग्री और योग्यता नहीं होती है। फर्जी डॉक्टर ऐसे मेडिकल स्टोर मालिकों को बढ़ावा देते हैं।

सानिया में महिला छात्राओं द्वारा इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या करना सरकारी व्यवस्था के लिए एक गंभीर घटना है। क्या मनमाने ढंग से मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति देने वाले अधिकारियों ने कभी इन स्टोरों का दौरा किया है? ये अधिकारी केवल दिवाली और होली जैसे त्योहारों के दौरान ही छिपने जाते हैं। ऐसे मेडिकल स्टोरों में सिरप की बिक्री अधिक होती है। और मजदूर इन स्टोरों से सिरप और नशीली गोलियां खरीदते हैं। यदि सरकारी अस्पताल और सरकारी अधिकारी सतर्क रहें, तो वे मेडिकल स्टोरों में काम करने वाले कई अयोग्य कर्मचारियों को पकड़ सकते हैं और इन स्टोरों को बंद करवा सकते हैं। डेली न्यूजलाइन डायरेक्ट न्यूज गुजराती के फोटोग्राफर और डेली गरवी गुजरात हिंदी की टीम इस क्षेत्र में ऐसे अयोग्य डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को बंद करवाने के लिए जानकारी जुटाएंगे और सभी फोटोग्राफिक और वीडियो सबूतों के साथ स्वास्थ्य मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और उन्हें इस मामले की जानकारी देंगे और कार्रवाई करने की अपील करेंगे।

सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये का अनुदान मिलने के बावजूद दवाओं की कमी है और गरीब मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में फंसे अधिकारियों को रिहा किया जाना चाहिए।

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

ई- निविदा सूचना

निविदा संख्या: EL/TRD/58/2x25/EPC-PSI/01, दिनांक: 10.03.2026. कार्य का नाम: Design, Supply, Erection, Testing and Commissioning of 132/55KV Scott Connected Traction Substation and Switching Posts for 2x25KV feeding system between Godhra-Ratlam section of Ratlam Division of Western Railway. **अनुमानित लागत:** रु. 146,06,00,000/-. **बयाना राशि:** रु. 74,53,000/-. **समापन अवधि:** 24 Months. **निविदा दस्तावेज़ की राशि:** Nil. **ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय:** 25.03.2026 upto 15:00 hrs की जगह 10.04.2026 upto 15:00 hrs. **तकनीकी बोलियां खोलने की की दिनांक एवं समय:** 06.04.2026 upto 15:30 hrs की जगह 21.04.2026 upto 15:30 hrs. **ऑफर की वैधता:** 180 days from the date of opening. **वेबसाइट: www.ireps.gov.in नोटिस बोर्ड:** वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने। DE/13/1/503

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

मार्च में ही तपने लगा देश: दिल्ली में पारा 36 पार, राजस्थान-गुजरात में लू का खतरा, पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी से मौसम का बदला मिजाज

जीएनएस)। मार्च का महीना अभी आधा भी नहीं बीता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आमतौर पर यह समय हल्की गर्माहट और बसंती मौसम का माना जाता है, लेकिन इस बार गर्मी ने समय से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर-पश्चिम और पश्चिम भारत के कई राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और कुछ स्थानों पर तो हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि मानो मई-जून जैसी गर्मी का अहसास होने लगा हो। दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिससे वहां के मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल सकते हैं—कहीं तेज गर्मी, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने मार्च के शुरुआती दिनों में ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आसमान में हल्के बादल रहने की संभावना है, लेकिन दिन के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है। सुबह और देर रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, गर्मी का असर बढ़ता जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले चार दिनों तक राजधानी में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। दिन में गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंडक के बीच लोगों को मौसम के इस उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।

राजस्थान में इस समय गर्मी का प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। राज्य के कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। मंगलवार को बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मार्च के महीने में ही 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है। इसके अलावा झुंझुनू जिले के पिलानी में तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चित्तौड़गढ़, चूरू, बीकानेर और सीकर के फतेहपुर में भी तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दिया, जहां अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ सकता है। हालांकि 12 मार्च के बाद तापमान में हल्की गिरावट आने के संकेत भी दिए गए हैं, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

गुजरात में भी मौसम का रुख तेजी से गर्म होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति बनने की चेतावनी जारी की है। खासकर पश्चिमी गुजरात और तटीय इलाकों में 11 से 13 मार्च के बीच गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना जताई गई है। समुद्र के नजदीक होने के कारण यहां तापमान के साथ उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है।

उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम का बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 मार्च के दौरान जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। घाटी के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इसी तरह 11 से 15 मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 11 और 12 मार्च को गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम और भी ठंडा महसूस हो सकता है।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने 11 से 16 मार्च के बीच इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 और 16 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान में 14 मार्च को और पूर्वी राजस्थान में 14 और 15 मार्च को हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। यदि ऐसा होता है तो इससे बढ़ते तापमान पर कुछ हद तक नियंत्रण लग सकता है।

देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भी मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में अलग-अलग दिनों में गरज-चमक के साथ आंधी आने की संभावना जताई गई है। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मौसम का रुख सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में पहले से ही नमी अधिक रहने के कारण बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी प्रणालियों के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की यह विविधता देखने को मिल रही है।

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी ने लंबे समय से चले आ रहे सूखे के बीच कुछ राहत जरूर दी है। कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। श्रीनगर समेत कई इलाकों में सुबह तक हल्की बारिश जारी रही। पिछले कुछ महीनों से राज्य में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई थी, जिससे जल स्रोतों और कृषि पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई थी।

दरअसल दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच जम्मू-कश्मीर में सामान्य से करीब 65 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई थी। इस अवधि में केवल 100.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर इस समय 284.9 मिलीमीटर वर्षा होती है। ऐसे में हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी को राहत की खबर माना जा रहा है। इससे जल स्रोतों के पुनर्जीवित होने और खेती को कुछ फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति पर अभी भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। यदि आने वाले समय में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो जल संकट और कृषि पर असर पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ही स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक त्रासदी: मां ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, दो मासूम बच्चों के शव कुएं में मिलने से गांव में पसरा सन्नाटा

जीएनएस)। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को शोक और स्तब्धता में डुबो दिया है। कपासन थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में हुई इस घटना ने हर किसी को भीतर तक हिला दिया। एक मां ने पहले अपने दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस त्रासदी ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे गांव के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर एक मां को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए किस दर्द या मजबूरी ने मजबूर कर दिया।

यह घटना कपासन थाना क्षेत्र के कछिया खेड़ी गांव की बताई जा रही है। यहां रहने वाले पारस कच्छावा की पत्नी अनछि बाई ने मंगलवार को उदयपुर से दिल्ली जा रही चेतक एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जब ट्रेन गांव के पास से गुजर रही थी, उसी समय महिला अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंची और ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। ट्रेन की तेज रफ्तार के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस भयावह दृश्य को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत घटना की सूचना अन्य ग्रामीणों तथा पुलिस को दी गई।

घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गए। ग्रामीणों ने जब मृत महिला की पहचान की तो पता चला कि वह गांव के ही निवासी पारस कच्छावा की पत्नी अनछि बाई है। लोगों के मन में उस समय और अधिक चिंता तब पैदा हुई जब यह पता चला कि महिला के साथ उसके दो छोटे बच्चे भी घर से निकले थे, लेकिन घटनास्थल पर वे दिखाई नहीं दे रहे थे। इस बात ने पूरे गांव में बेचैनी बढ़ा दी। ग्रामीणों को आशंका होने लगी कि कहीं बच्चों के साथ भी कोई अनहोनी न हो गई हो।

महिला के दोनों बच्चों की पहचान मोनू और सोनू के रूप में हुई। मोनू की उम्र करीब पांच वर्ष बताई जा रही है, जबकि सोनू मात्र तीन वर्ष का था। दोनों बच्चे काफी छोटे थे और गांव के लोगों के बीच अक्सर खेलते-कूदते दिखाई देते थे। जब बच्चों के घटनास्थल पर न मिलने की जानकारी सामने आई तो ग्रामीणों ने तुरंत उनकी तलाश शुरू कर दी। गांव के आसपास के खेतों, रास्तों और सुनसान जगहों पर खोजबीन शुरू कर दी गई। इसी दौरान किसी की नजर गांव के बाहर स्थित एक पुराने कुएं पर पड़ी।

जब लोगों ने कुएं के भीतर झांककर देखा तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कुएं के भीतर दो छोटे बच्चों के शव दिखाई दे रहे थे। यह खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से दोनों बच्चों के शव बाहर निकलवाए। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला ने पहले अपने दोनों बच्चों को कुएं में डाल दिया और उसके बाद खुद रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी।

घटना की सूचना मिलते ही कपासन के पुलिस उपाधीक्षक हरजी लाल यादव और थाना अधिकारी सुनील शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने महिला और दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर कपासन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अधिकारियों के अनुसार तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। जिन लोगों ने मोनू और सोनू को खेलते-कूदते देखा था, उनके लिए यह विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सभी इस घटना को लेकर बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति रही होगी, जिसने एक मां को अपने ही बच्चों के साथ इतना भयावह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला के जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण उसने इतना बड़ा और दुखद निर्णय लिया। इसके लिए पुलिस परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों से बातचीत कर रही है।

ऑपरेशन 'अमानत' के तहत यात्री का यात्रा में छूटा आई-फोन सुरक्षित लौटाया गया

जीएनएस)। भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा एवं उनकी खोई हुई वस्तुओं को वापस दिलाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन अमानत' के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में एक बार फिर तत्परता और संवेदनशीलता का उदाहरण देखने को मिला, जब यात्रा के दौरान सीट पर छूट गया एक यात्री का महंगा आई-फोन आरपीएफ द्वारा खोजकर सुरक्षित रूप से यात्री को लौटा दिया गया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 10 मार्च 2026 को यात्री श्री धवल ट्रेन संख्या 12927 एकतानगर–दादर एक्सप्रेस के कोच संख्या A-2 में दादर से वडोदरा की यात्रा कर रहे थे। वडोदरा स्टेशन पर उतरने के बाद जब वे स्टेशन से बाहर चले गए, तब उन्हें पता चला कि उनका आई-फोन ट्रेन की सीट पर ही छूट गया है।

यात्री द्वारा तत्काल रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर इसकी सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की एकतानगर पोस्ट पर कार्यरत कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार तथा कांस्टेबल महेश चंद शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एकतानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म लाइन संख्या 05 पर खड़ी उक्त ट्रेन के कोच संख्या A-2 की जांच की। जांच के दौरान मोबाइल फोन सीट पर सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ।

यात्री द्वारा बताए गए विवरण से मोबाइल का मिलान करने तथा आवश्यक सत्यापन के उपरांत हेड कांस्टेबल सतेंद्र कुमार द्वारा उक्त आई-फोन संबंधित यात्री को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया। अपना मोबाइल सुरक्षित वापस मिलने पर यात्री श्री धवल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा संचालित रेल मदद 139 हेल्पलाइन की त्वरित एवं प्रभावी सेवा की सराहना की। साथ ही उन्होंने आरपीएफ एकतानगर पोस्ट की तत्परता तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन अमानत' के सराहनीय कार्यों की भी प्रशंसा की।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी वस्तु के छूट जाने या आपात स्थिति में तुरंत रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा 'ऑपरेशन अमानत' यात्रियों की खोई हुई वस्तुओं को खोजकर उन्हें सुरक्षित लौटाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य कर रहा है, जिससे यात्रियों में रेलवे के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ़ हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ग्रामीण नागरिकों तथा किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

- प्रॉमल्गेशन हुए गाँवों के मापन की क्षति में सुधार के आवेदनों का समग्र राज्य में एक समान पद्धति तथा योजनाबद्ध निस्तारण भूमि सीमांकन से किया जाएगा
- मुख्यमंत्री के निर्णय से गुड गवर्नेंस द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वेग मिलेगा
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिलों में भूमि सीमांकन समिति कार्यरत होंगी
- प्रॉमल्गेशन के बाद आए क्षति सुधार आवेदनों के योजनाबद्ध निस्तारण के लिए सात श्रेणियाँ निर्धारित की गईं
- मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट समिति क्षति सुधार की जटिल समस्याओं का नियमानुसार कार्यवाही कर त्वरित निवारण लाएगी

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रॉमल्गेशन (प्रख्यापित) हुए गाँवों में मापन अंतर्गत रह गईं क्षतियों में सुधार के आवेदनों का एक समान पद्धति तथा योजनाबद्ध ढंग से निस्तारण करने के लिए भूमि सीमांकन के स्पष्ट दिशा-निर्देश राजस्व विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के जरिये कृषि भूमि के मापन में प्रख्यापन के बाद किसानों के आपत्ति आवेदनों का निस्तारण पारदर्शी एवं सटीकतापूर्वक ढंग से करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वेग देने के साथ ग्रामीण किसानों के हितों की रक्षा करने का किसान कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया है।

उन्होंने भूमि सीमांकन अंतर्गत राज्य के जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में भूमि सीमांकन समिति कार्यरत करने तथा जिलों के भूमि सीमांकन कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

इन जिला स्तरीय समितियों में कलेक्टर के अलावा निवासी अपर कलेक्टर, भूमि उप निदेशक (एसएलआर) कार्यालय, प्रांत अधिकारी, डीआईएलआर, तहसीलदार, टीडीओ, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सरदार सरोवर पुनर्वास एजेंसी या अन्य अधिग्रहण संस्था के प्रतिनिधि का समावेश किया जाएगा।

भूमि सीमांकन अंतर्गत प्रख्यापन के बाद मापन की क्षति में सुधार के लिए आए आवेदनों के योजनाबद्ध एवं सुचारु निवारण के लिए मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश के चलते राजस्व विभाग द्वारा लगभग सात अलग-अलग श्रेणियाँ (कैटेगरीज) निर्धारित की गई हैं।

तद्अनुसार; (1) सरकारी/जन हित की जमीनों में कमी न हुई हो तथा कोई आपत्ति दर्ज न हुई हो (2) सरकारी/जन हित की जमीनों में कमी न हुई हो तथा कोई आपत्ति शेष न हो और कोई खातेदार को आपत्ति न हो (3) सरकारी/जन हित की जमीनों में कमी न हुई हो तथा आपत्ति आवेदन लंबित हो (3ए) सरकारी/जन हित की जमीनों में कमी हुई हो तथा आपत्ति आवेदन लंबित हों (4) गाँव के 30 प्रतिशत से अधिक सर्वे नंबरों में स्वामित्व परिवर्तन (प्रथम-अंतिम) (5) गाँव की आपत्तियाँ एक क्षेत्र तक सीमित हों (6) 30 प्रतिशत से अधिक सर्वे नंबरों में क्षेत्रफल में परिवर्तन तथा कैस्केडिंग इफेक्ट एवं आकृति में अधिक परिवर्तन (7) प्रख्यापन न हुआ हो। इस तरह की सात श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भूमि सीमांकन अंतर्गत मापन क्षति सुधार की जटिल समस्याओं का त्वरित निवारण हो और साथ ही आवेदकों को कार्यालय में न जाना पड़े; इसके लिए तहसील विकास अधिकारी, तहसीलदार को अधिक अधिकार देकर मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट समिति के जरिये गुजरात भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 119, 120 तथा भूमि राजस्व नियम, 1972 के नियमों 21(1), 21(2) व 21(3) के अनुसार कार्यवाही कर निवारण लाने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने ऐसी मापन क्षति सुधार की अधिकतम समस्याओं का भूमि सीमांकन अंतर्गत राज्यभर में एक समान कार्यपद्धति से तेजी और पारदर्शी ढंग से निवारण लाकर लोगों को सुशासन की सटीक व प्रभावी अनुभूति हो; ऐसा कार्य करने के लिए राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं।

भावनगर मंडल में मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (DRUCC) की बैठक संपन्न

जीएनएस)। यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा रेल सेवाओं से संबंधित सुझावों पर विचार-विमर्श के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (DRUCC) की बैठक का आयोजन दिनांक 11 मार्च, 2026 (बुधवार) को मंडल कार्यालय में किया गया। बैठक का शुभारंभ समिति के सचिव एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए भावनगर मंडल में अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे स्टेशनों की प्रगति एवं प्रस्तावित यात्री सुविधाओं की विस्तृत जानकारी साझा की।

इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने भावनगर मंडल में चल रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों, परियोजनाओं तथा हाल की उपलब्धियों के बारे में सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएँ प्रदान करना मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त सभी उचित सुझावों एवं मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से भावनगर मंडल की उपलब्धियों, चल रही परियोजनाओं तथा यात्री सुविधाओं में किए जा रहे सुधारों की जानकारी दी गई। समिति के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित रेल समस्याओं, नई ट्रेनों के संचालन, लंबित परियोजनाओं की शीघ्र पूर्ति तथा स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

बैठक में समिति के सदस्य श्री किरण एम. गांधी(भावनगर), श्री बैजु एस. मेहता (भावनगर), श्री महेन्द्र शाह (भावनगर), श्री उपेन्द्रभाई जानी (भावनगर), श्री प्रदीपभाई एच. देसाई (भावनगर), श्री पारसभाई सी. शाह (भावनगर), डॉ. आर. सी. गुप्ता (भावनगर), श्री प्रविणसिंह बी. झाला (सुरेन्द्रनगर), श्री अनिष एन. राच्छ (वेरावल), श्री जिग्नेश कारिया (पोरबंदर) तथा श्री एस. ए. सिंह (अधीक्षक इंजीनियर, गांधीनगर) उपस्थित रहे। बैठक के समापन पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने सभी सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझावों एवं सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए भावनगर मंडल में हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर (HABD) की स्थापना

जीएनएस)। यात्रियों की सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेल यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल करते हुए हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर (HABD) प्रणाली की स्थापना एवं सफलतापूर्वक कमीशनिंग की गई है।

यह अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली मंडल के निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित की गई है —

- मोटा सुरखा
- आद्री रोड
- सारंगपुर रोड

हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर (HABD) एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली है, जो ट्रेन के संचालन के दौरान प्रत्येक कोच एवं वैगन के एक्सल बॉक्स के तापमान की निरंतर निगरानी करती है। यदि किसी एक्सल बॉक्स का तापमान निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, तो यह प्रणाली तुरंत अलर्ट जारी करती है। इससे संभावित तकनीकी खराबी का समय रहते पता लगाया जा सकता है तथा आवश्यक कार्यवाही कर दुर्घटनाओं की संभावना को टाला जा सकता है।

इस प्रणाली के माध्यम से:

- चलती ट्रेनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होती है।
- हॉट एक्सल की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान की जा सकती है।
- ट्रेन संचालन की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।
- यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुरक्षित एवं आरामदायक बनाया जा सकता है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा की प्रेरणा व मार्गदर्शन से एवं वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री संतोष कुमार मिश्रा की देखरेख में भावनगर मंडल के यांत्रिक विभाग द्वारा इस परियोजना का सफल क्रियान्वयन किया गया है। इस अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना से मंडल में ट्रेन संचालन की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है। भावनगर मंडल निरंतर आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, कुशल एवं यात्री हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। HABD प्रणाली की स्थापना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो संभावित तकनीकी जोखिमों की समय रहते पहचान कर रेल परिचालन को और अधिक सुरक्षित बनाएगी।

गुजरात सरकार ने अहमदाबाद और सूरत मेट्रो के लिए कुल 34 अत्याधुनिक ट्रेन सेट के ऑर्डर दिए : अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 के लिए मिलेंगे 10 और ट्रेन सेट

- अहमदाबाद-गांधीनगर कॉरिडोर के यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ेंगे मेट्रो के फेरे
- गुजरात में अभी 108 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क, आगामी वर्षों में 190 किमी तक विस्तार का अनुमान

जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात सरकार ने 34 अत्याधुनिक मेट्रो ट्रेन सेट बनाने का ऑर्डर दिया है, जिसमें अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 के लिए 10 ट्रेन सेट और सूरत मेट्रो के लिए 24 ट्रेन सेट शामिल हैं। ये ट्रेनें कोलकाता स्थित टीटागढ़ की अद्यतन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाई जा रही हैं, जो हाई-टेक अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। यह पहल गुजरात में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही देश की उत्पादन क्षमताओं को भी उजागर करेगी। इससे न केवल रोजगार और कौशल विकास के अवसर खुलेंगे, बल्कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में मेट्रो रेल शुरू करने का स्वप्न देखा था, और उनके मार्गदर्शन में गुजरात में अहमदाबाद और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। आज, उनके सुदृढ़ मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-1 और फेज-2 सफलतापूर्वक शुरू हो चुके हैं और अहमदाबाद एवं गांधीनगर के लाखों लोग मेट्रो रेल का लाभ उठा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात शहरी परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 के अंतर्गत अहमदाबाद-गांधीनगर कॉरिडोर में 68.2 किमी का मेट्रो नेटवर्क पहले से ही कार्यरत है, जिसमें अभी 32 ट्रेन सेट सेवा में हैं। इसमें 10 और ट्रेन सेट जुड़ने से यात्रियों के सुगम परिवहन के लिए ट्रेनों के फेरे बढ़ जाएंगे, इंतजार करने का समय कम हो जाएगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

अभी सूरत में 40.3 किमी लंबे मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूरत मेट्रो के लिए 24 ट्रेन सेट का ऑर्डर दिया गया है, जिसके पूरा होने के बाद सूरत शहर टिकाऊ शहरी परिवहन के मजबूत विस्तार का गवाह बनेगा। यह विकास परिवहन सुविधा को आसान बनाएगा, भीड़ को कम करेगा और सूरत की बढ़ती शहरी आबादी के लिए लाभकारी बनेगा।

गुजरात राज्य में मेट्रो रेल नेटवर्क अभी 108 किमी तक फैला हुआ है, और आगामी वर्षों में इसका विस्तार 190 किमी तक होने का अनुमान है। इसमें 6.04 किमी की पूर्व नियोजित एयरपोर्ट लाइन भी शामिल है, जो कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इसके अलावा, राजकोट और वडोदरा जैसे दूसरे मुख्य शहरों में भी मेट्रो रेल सेवाओं का विस्तार करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधुनिक, कुशल और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के लाभ राज्य भर में अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंच सकें।

गुजरात में नया मेट्रो सिस्टम अत्याधुनिक ड्राइवरलेस (चालक रहित) टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होगा, जो समय-पालन, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ट्रेनों में रियल-टाइम मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, ऑप्टिमाइज्ड स्पीड प्रोफाइल्स और इंटेलिजेंट फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स जैसी प्रणालियां होंगी, जो विश्वसनीय संचालन की गारंटी देती हैं।

इसके अतिरिक्त, सीसीटीवी सर्विलांस, फायर डिटेक्शन सिस्टम, फेल-सेफ डोर ऑपरेशंस और ऑब्स्टेकल डिटेक्शन यानी अवरोधों का पता लगाने वाली प्रणालियों जैसे यात्री-केंद्रित सुधार यात्रियों को सुरक्षित और आसान यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगे। ये नई विशेषताएं गुजरात की मेट्रो ट्रेनों को आधुनिक, स्मार्ट और टिकाऊ शहरी परिवहन के मॉडल के रूप में स्थापित करेंगी।

एक्सप्रेसवे से लेकर हाई-स्पीड रेल तक, गुजरात भारत की परिवहन अवसंरचना के विकास में लगातार अग्रणी रहा है। गुजरात का आगामी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, दाहोद में भारत का पहला 9000 एचपी लोकोमोटिव इंजन का उत्पादन करने वाला संयंत्र और नमो भारत ट्रेन इसके मजबूत उदाहरण हैं। गुजरात के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट समय पर कार्यान्वयन, तकनीकी नवाचार और टिकाऊ शहरी विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का शानदार उदाहरण हैं। गुजरात ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विकास के जरिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करने के विजन को साकार करने में अहम योगदान दे रहा है।